

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा,

निदेशक,  
जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान  
गोपेश्वर चमोली।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 03 अगस्त, 2015

विषय:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा "कपकोट में प्रदेश के जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान के उपकेन्द्र की स्वीकृति प्रदान की जायेगी" हेतु पूर्व से स्वीकृत/अवमुक्त ₹25 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-344/ज०बू०सं०/2015-16 दिनांक-13 अगस्त 2015 तथा सचिवालय प्रशासन (लेखा अनुभाग-4) के शासनादेश संख्या-184/XXXI(12)/2014-15 दिनांक-23 मार्च 2015 के द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त ₹25 लाख की धनराशि जनपद बागेश्वर के कपकोट में प्रदेश के जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान के उपकेन्द्र खोले जाने हेतु आप द्वारा किये गये प्रस्ताव के क्रम में मा० मुख्यमंत्री की घोषणा मद से पूर्व में अवमुक्त ₹ 25.00 लाख (₹ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि की व्यय हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त घोषणा के क्रियान्वयन करते समय वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-318/XXVII(1)/2014 दिनांक-18 मार्च 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (2) किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया(स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्ठादन नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) इसके अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
- (4) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

क्रमशः....2



- (5) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।
- (6) उक्त घोषणान्तर्गत जहाँ पर वृहद निर्माण कार्य कराये जाने हों, ऐसी स्थिति में कार्यों का आगणन गठित कर यथा नियम टी0ए0सी0 वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाय।
- (7) योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा-निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- (8) वृहद निर्माण कार्यों के आगणन बनाकर उस पर शासन का अनुमोदनोपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।
- (9) इस धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 886 (1)/XVI-2/15/02(C.M घोषणा)/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
- 2— निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन चौबटिया—रानीखेत।
- 3— जिलाधिकारी, चमोली / टिहरी।
- 4— वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली / टिहरी।
- 5— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, देहरादून।
- 6— राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)  
अपर सचिव।